एस. पी. एस. रथोर

वी.

सी. बी. आई. और ए. एन. आर.

(2010 की आपराधिक अपील सं. 2126)

23 सितंबर, 2016

[वी. गोपाल गौड़ा और आर. के. अग्रवाल, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:

एस.354 – आवश्यक सामग्री-चर्चा की गई-तत्काल मामले में, अपीलकर्ता-आरोपी, राज्य के एक बहुत ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की-पीडब्लू-13 ने देखा कि पीड़ित की पकड़ में थी अपीलार्थी-अभियुक्त जो पीड़ित का एक हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए था और उसका दूसरा हाथ उसकी कमर के आसपास था और वह उसे अपनी छाती की ओर खींच रहा था ताकि उसे गले लगा सके जबकि पीड़ित कोशिश कर रहा था उसे अपने स्वतंत्र हाथ से पीछे धकेलने के लिए-पीडब्लू-13 ने शुरू से अंत तक उसकी गवाही का सामना किया और उसके बयान को अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के साथ विश्वसनीय और पुष्टि करने वाला पाया गया-नीचे की दोनों अदालतों ने अपीलकर्ता-अभियुक्त यू/एस को सही तरीके से दोषी ठहराया। 354 भा.दं.सं. सी.-महिलाओं के खिलाफ अपराध-एक महिला की शील भंग करना।

एस.354 – छेड़छाड़ की शिकायत प्रस्तुत करने में देरी-आयोजितःतत्काल मामले में, अपीलार्थी-अभियुक्त, बहुत वरिष्ठ था।राज्य के पुलिस अधिकारी-पीड़ित अविवाहित नाबालिग लड़की थी-सामान्य रूप से मानवीय आचरण के क्रम में, यह अविवाहित नाबालिग लड़की, उस दर्दनाक अनुभव का प्रचार नहीं करना चाहेगी जो उसने किया था

और इस घटना के संबंध में उसे बताने के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस करती थी उसके माता-पिता और अन्य लोगों के लिए शर्म की भावना और उसका स्वाभाविक झुकाव किसी से भी इसके बारे में बात करने से बचना होगा, ऐसा न हो कि परिवार का नाम और सम्मान विवाद में आ जाए-देरी शिकायत प्रस्तुत करने के लिए 6 दिनों का समय दिया गया है और इसलिए यह क्षमा योग्य है।.

आपराधिक कानूनः

यह ज्ञान कि यह कार्य एक अपराध करने के बराबर है-आयोजितःयदि इरादा या ज्ञान किसी अपराध के घटकों में से एक है, तो इसे दोषी ठहराने के लिए अन्य घटकों की तरह साबित करना होगा। एक व्यक्ति-लेकिन, यह भी उतना ही सच है कि मन की स्थिति होने के कारण उन तत्वों को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता है और किसी दिए गए मामले की उपस्थित परिस्थितियों से उनका अनुमान लगाना पड़ सकता है।

प्रमाणः

अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष-आयोजितःइसे केवल तभी तैयार किया जा सकता है जब यह कुछ सबूतों को रोकता है, न कि केवल कुछ सबूत प्राप्त करने में अपनी विफलता के कारण।

हस्ताक्षर विशेषज्ञ- का प्रमाणिक मूल्य-आयोजितः एक हस्तलेखन विशेषज्ञ का अप्रमाणित साक्ष्य एक अत्यंत कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और उसी पर दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के लिए भरोसा नहीं किया जाना चाहिए-इसलिए, अदालतों को हस्तलेखन विशेषज्ञ के साक्ष्य को बहुत अधिक महत्व देने के लिए सावधान रहना चाहिए-यह शायद ही कभी, यदि कभी भी, ठोस साक्ष्य की जगह ले सकता है-ऐसे साक्ष्य पर कार्रवाई करने से पहले, यह देखना सामान्य है कि क्या यह स्पष्ट, प्रत्यक्ष साक्ष्य या

परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा पुष्टि की जाती है।

एकमात्र चश्मदीद गवाह-का प्रमाणिक मूल्य-आयोजितःएक निश्चित तथ्य को साबित करने के लिए गवाहों की किसी विशेष संख्या की आवश्यकता नहीं है-यह गुणवत्ता है न कि गवाहों की संख्या जो मायने रखती है-साक्ष्य तौला जाता है और गिना नहीं जाता है-एक भी चश्मदीद गवाह का साक्ष्य, सच्चा, सुसंगत और प्रेरक विश्वास दृढ़ विश्वास बनाए रखने के लिए पर्याप्त है-यह आवश्यक नहीं है कि वे सभी व्यक्ति अभियुक्त के अपराध को साबित आदेशने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की जानी चाहिए।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1, भा.दं.सं. सी. की खंड 354 के तहत अपराध का गठन आदेशने के लिए, केवल यह जानना कि एक महिला की शील भंग होने की संभावना है, केवल अपने उद्देश्य के लिए इस तरह का आक्रोश आदेशने के किसी भी जानबूझआदेश इरादे के बिना पर्याप्त है।विनम्रता की कोई संक्षिप्त सार अवधारणा नहीं है जो सभी मामलों पर लागू हो सकती है।भा.दं.सं. सी. की खंड 354 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व निम्नानुसार हैंः

> (i) कि हमला किया गया व्यक्ति एक महिला होनी चाहिए; (ii) कि आरोपी ने उस पर आपराधिक बल का इस्तेमाल किया होगा; और (iii) कि महिला पर आपराधिक बल का इस्तेमाल उसकी शील भंग करने के इरादे से किया गया होगा।यदि इरादा या ज्ञान किसी भी अपराध के घटकों में से एक है, तो इसे किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अन्य घटकों की तरह साबित करना होगा।लेकिन, यह भी उतना ही सच है कि मन की स्थिति होने के कारण उन तत्वों को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता है और

किसी दिए गए मामले की उपस्थित परिस्थितियों से उनका अनुमान लगाना पड़ सकता है।तत्काल मामले में घटनाओं का क्रम इंगित करता है कि अपीलार्थी- अभियुक्त का अपेक्षित दोषपूर्ण इरादा था। [पारस 22,24] [354-एफ-एच; 355-डी]

2. एस. एच. ओ. को शिकायत प्रस्तुत करने में लगभग 6 दिनों की देरी के संबंध में, इसे विधिवत समझाया गया है।भारत में एक परंपरा से बंधे गैर-अनुमति समाज में, यह स्वीकार करने में बेहद हिचकिचाहट होगी कि कोई भी घटना जो किसी महिला की पवित्रता को प्रतिबिंबित करने की संभावना है, समाज द्वारा बहिष्कृत होने या समाज द्वारा नीचा देखे जाने के खतरे के प्रति सचेत होने के कारण हुई थी।तत्काल मामले में, पीड़ित ने माता-पिता को इस परिस्थिति में घटना के बारे में सूचित नहीं किया कि अपीलार्थी-अभियुक्त, जो राज्य का एक बहुत ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, उचित था और उसके लिए बोलने का निर्णय आसान नहीं होता।उसके माता-पिता को घटना की सूचना देने के बाद, निवासियों और साथी खिलाड़ियों द्वारा तुरंत अनुवर्ती कार्रवाई की गई और अपीलकर्ता-आरोपी के खिलाफ आरोपों वाला एक ज्ञापन तैयार किया गया और तत्कालीन सचिव (गृह) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।इसलिए, अपीलार्थी-अभियुक्त पर उचित विचार करते हुए, एक बार जब पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों को वरिष्ठ अधिकारियों से न्यायाधीश का आश्वासन मिल गया, तो उन्होंने अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।[पैरा 26] [355-जी-एच; 356-ए, सी-डी]

3. अपीलार्थी-अभियुक्त ने तर्क दिया कि ज्ञापन पर पीड़ित के हस्ताक्षर जाली थे, हालांकि उसने शिकायतकर्ता और अन्य लोगों के हस्ताक्षर किए थे।किसी भी विशेषज्ञ के साक्ष्य पर कार्य करते हुए, यह आमतौर पर यह देखने के लिए होता है कि क्या उस साक्ष्य की पुष्टि या तो स्पष्ट, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा की

जाती है।एक हस्तलेखन विशेषज्ञ का एकमात्र साक्ष्य आम तौर पर किसी निश्चित व्यक्ति के लेखन के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है।एक अदालत किसी व्यक्ति के विवादित लेखन की तुलना दूसरों के साथ करने में सक्षम है जो उसके लेखन के रूप में स्वीकार या साबित होते हैं।किसी अदालत के लिए किसी व्यक्ति के लेखन के बारे में निष्आदेश को केवल विशेषज्ञ तुलना के आधार पर किसी निश्चित दस्तावेज में दर्ज आदेशना सुरक्षित नहीं हो सकता है, लेकिन एक अदालत स्वयं लेखन की तुलना आदेश सकती है ताकि उस संबंध में उसके सामने पेश किए गए अन्य साक्ष्यों की ठीक से सराहना की जा सके।एक हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय साक्ष्य अधिनियम की खंड 45 को देखते हुए भी प्रासंगिक है, लेकिन वह भी निर्णायक नहीं है।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक हस्तलेखन विशेषज्ञ का अप्रमाणित साक्ष्य एक अत्यंत कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और उसी पर दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के लिए भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।[पैरा 27,30] [356-डी-जी; 358-सी]

4. इस तर्क के संबंध में कि दो महत्वपूर्ण स्थल गवाहों, अर्थात् गेंद चुनने वाले और कोच से पूछताछ न करने से अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकलते हैं, उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष केवल तभी निकाला जा सकता है जब वह कुछ सबूतों को रोकता है, न कि केवल कुछ सबूत प्राप्त करने में विफलता के कारण।इसके अलावा, वे किसी भी तरह से अपराध के वास्तविक अपराध से जुड़े नहीं थे और उनकी अभावि में भी, अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा छेड़छाड़ के अपराध का अपराध चश्मदीद गवाह (पीडब्लू -13) घटना के लिए।[पैरा 32] [358-जी-एच; 359-ए]

5. एक निश्चित तथ्य को साबित करने के लिए गवाहों की कोई विशेष संख्या की आवश्यकता नहीं है।एक चश्मदीद गवाह का भी प्रमाण, सच्चा, निरंतर और प्रेरक आत्मविश्वास दृढ़ विश्वास बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।यह आवश्यक नहीं है कि

अभियुक्त के अपराध को साबित आदेशने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा उन सभी व्यक्तियों से पूछताछ की जानी चाहिए जो घटनास्थल पर मौजूद थे।पीडब्लू-13 ने शुरू से अंत तक उसकी गवाही का विरोध किया और उसके बयान को अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के साथ विश्वसनीय और पुष्टि करने वाला पाया गया और नीचे दी गई दोनों अदालतें भा.दं.सं. की खंड 354 के तहत अपीलार्थी-आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखने में सही थीं। [पारस 33,34] [359-बी, डी]

6. अपीलार्थी-अभियुक्त की सजा के संबंध में, कुछ कम करने वाले कारकों पर ध्यान दिया गया-अपीलार्थी-अभियुक्त की वृद्धावस्था, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित अविवाहित बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी, पिछली सराहनीय सेवा और लंबे समय तक मुकदमा।इन कारकों को विशेष रूप से अपीलार्थी-अभियुक्त की वृद्धावस्था और शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी-अभियुक्त की सजा को उसकी बहुत अधिक उम्र को देखते हुए एक विशेष मामले के रूप में पहले से गुजर चुकी अवधि तक कम कर दिया जाता है।[पैरा 35] [359-ई-एफ]

विद्याधरन बनाम केरल राज्य (2004) 1 एससीसी 215:2003 (5) पूरक।एस. सी. आर. 524; तारकेश्वर साहू बनाम बिहार राज्य (2006) 8 एस. सी. सी. 560:2006 (7) पूरक।एस. सी. आर. 10; मोबारक अली अहमद बनाम। राज्य।बॉम्बे एयर 1957 एस. सी. 857:1958 एस. सी. आर. 328; श्रीमती, भगवान कौर बनाम श्री महाराज कृष्ण शर्मा और अन्य। (1973) 4 एससीसी 46:1973 (2) एस. सी. आर. 702-निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

2003 (5) पूरक।एस. सी. आर. 524	पैरा 23	पर निर्भर था।
2006 (7) पूरक।एस. सी. आर. 10	पैरा 25	पर निर्भर था।
1958 एस. सी. आर. 328	पैरा 28	पर निर्भर था।

1973 (2) एस. सी. आर. 702 पैरा 29 पर निर्भर था।

आपराधिक अधिकार क्षेत्र न्यायनिर्णयः 2010 की दाण्डिक अपीलीय सं 2126।

आपराधिक मामले में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 01.09.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश से 2010 का संशोधन सं. 1558।

के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री प्रियांजली सिंह, धनंजय रे, मेहूल एम. गुप्ता, अधिवक्ता।अपीलकर्ता के लिए।

सुश्री विभा दत्ता मखीजा, वरिष्ठ अधिवक्ता, राजीव नंदा, अजय शर्मा, बी. वी. बलराम दास, अरविंद कुमार शर्मा, विकास मेहता, सुश्री अनुश्री मेनन, अधिवक्ता। प्रतिवादीओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. के. अग्रवाल, जे. 1.यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा 2010 के आपराधिक संशोधन संख्या 1558 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 01.09.2010 के खिलाफ दायर की गई है। जिससे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया

2. संक्षिप्त तथ्यः

क) एस. पी. एस. राठौर-अपीलार्थी- अभियुक्त, देश की प्रतिष्ठित सेवा के सदस्य, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी. बी. एम. बी.), चंडीगढ़ में निदेशक (सतर्कता और सुरक्षा) के रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे। उन्होंने वर्ष 1988 में हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन (एचएलटीए) की भी स्थापना की।

(ख) एच. एल. टी. ए. का कार्यालय हाउस नं. 469, सेक्टर 6,

पंचकूला के गैराज में स्थापित किया गया था, जो अपीलार्थी-अभियुक्त के स्वामित्व वाली एक निर्माणाधीन इमारत थी, जिसे तीन भागों में विभाजित किया गया था जिसमें सामने वाले हिस्से का उपयोग एच. एल. टी. ए. के कार्यालय के रूप में किया जा रहा था और अन्य दो भागों का उपयोग टी. थॉमस और कुलदिप सिंह, कोच और मैनेजर, एसोसिएशन द्वारा आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था।एच. एल. टी. ए. ने मासिक सदस्यता के भुगतान पर कई सदस्य खिलाड़ियों को नामांकित किया जो ज्यादातर पंचकूला के आस-पास के निवासी थे।

(ग) सुश्री रुचिका (मृत होने के बाद से), बेटी श्री एस सी. गिरहोत्रा और सुश्री आराधना उर्फ रीमू, श्री आनंद प्रकाश और मधु प्रकाश (शिकायतकर्ता) की बेटी, दोनों की उम्र लगभग 15 वर्ष है, पंचकूला के निवासियों ने खुद को एच.एल.टी.ए. के सदस्यों के रूप में नामांकित किया। दोनों अच्छे दोस्त थे। टेनिस कोर्ट में अभ्यास करने के लिए एक साथ जाते थे। अपीलार्थी- अभियुक्त भी उक्त टेनिस कोर्ट में अक्सर आता था। एक दिन जब सुश्री रुचिका ने अपीलार्थी-अभियुक्त को विदेश जाने की अपनी योजना के बारे में सूचित किया, तो अपीलार्थी- अभियुक्त ने अपने पिता- श्री एस.सी.गिरहोत्रा से आई.डी. 1 पर मुलाकात की ताकि उन्हें अपनी बेटी को विशेष टेनिस कोचिंग के लिए देश से बाहर नहीं भेजने के लिए राजी किया जा सके और वादा किया कि उनके लिए एच.एल.टी.ए. में ही विशेष कोचिंग की आदेश की जाएगी और उसी संबंध में अगले ही दिन रुचिका को अपने कार्यालय भेजने के लिए भी कहा। श्री गिरहोत्रा ने अपनी बेटी रुचिका को इसकी सूचना दी और उसे 12.08.1990 पर अपीलार्थी-अभियुक्त से उसके कार्यालय में मिलने के लिए कहा।

(घ) 12.08.1990 पर, सुश्री रुचिका ने सुश्री आराधना के घर का दौरा किया और उन्हें अपीलार्थी-अभियुक्त के उनके घर आने के बारे में बताया और यह भी बताया कि उसने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया था। जब वे दोनों टेनिस कोर्ट में अभ्यास कर रहे थे, तो बॉल पिकर पलटू ने सुश्री रुचिका को सूचित किया कि अपीलार्थी- आरोपी ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया था। तदनुसार, सुश्री रुचिका सुश्री आराधना के साथ अपीलार्थी-अभियुक्त से मिलने गई जो उस विशेष समय कार्यालय के बाहर खड़ा था। अपीलार्थी-अभियुक्त ने उन्हें कार्यालय के अंदर आने के लिए जोर दिया। उसके आग्रह पर दोनों लड़कियाँ कार्यालय के अंदर चली गईं। अपीलार्थी- अभियुक्त एक कुर्सी ले आया जिस पर सुश्री आराधना थी और सुश्री रुचिका सुश्री आराधना की दाहिनी ओर खड़ी थी जबकि अपीलार्थी-अभियुक्त अपनी कुर्सी पर बैठा था जो मेज के दूसरी तरफ थी।अपीलार्थी-अभियुक्त ने सुश्री आराधना से श्री थॉमस-द कोच को बुलाने का अनुरोध किया। तदनुसार, सुश्री आराधना अपीलार्थी- अभियुक्त और सुश्री रुचिका को कार्यालय में छोड़कर बाहर चली गईं। सुश्री आराधना ने कार्यालय में अपने लिए कुर्सी लाने वाले व्यक्ति से अपीलार्थी-अभियुक्त के कार्यालय में आने के लिए प्रशिक्षक को सूचित करने के लिए कहा। लेकिन कोच ने आने से इनकार कर दिया।

(ङ) इसके तुरंत बाद, जब सुश्री आराधना कार्यालय लौटी, तो उन्होंने देखा कि सुश्री रुचिका अपीलार्थी- अभियुक्त की पकड़ में थी, जो रुचिका का एक हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए थी और उसका दूसरा हाथ उसकी कमर में था। अपीलार्थी-अभियुक्त उसे अपनी छाती की ओर खींच रहा था ताकि उसे गले लगा सके और रुचिका अपने खाली हाथ से उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी।

(च) सुश्री आराधना (पीडब्लू-13) को देखकर, अपीलार्थी-अभियुक्त डर गया और सुश्री रुचिका को छोड़ दिया और अपनी कुर्सी पर गिर गया। अपीलार्थी-अभियुक्त ने सुश्री आराधना को फिर से अपने कमरे से बाहर जाने और व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षक को अपने साथ लाने के लिए कहा। अपीलार्थी-अभियुक्त रुचिका को अपने कमरे में रहने के लिए जोर देता था, लेकिन वह किसी तरह भागने में सफल रही। जब आराधना रुचिका के पीछे जाने वाली थी, तो अपीलार्थी-अभियुक्त ने उससे कहा, "उसे शांत होने के लिए कहें, वह जो कहेगी मैं वही करूंगी।"यह सुनने के बाद, सुश्री आराधना भी मामले के बारे में पूछताछ करने के लिए सुश्री रुचिका के पीछे दौड़ी। इसके बाद रुचिका ने उसे पूरी घटना सुनाई। चर्चा के बाद, दोनों लड़कियों ने अपने माता-पिता को इसकी सूचना नहीं देने का फैसला किया क्योंकि अपीलकर्ता-आरोपी, पुलिस का आई. जी होने के नाते, उन्हें और उनके माता-पिता को शामिल या परेशान कर सकता है।

(छ) 14.08.1990 पर, सुश्री रुचिका, सुश्री आराधना के साथ लगभग 4 बजे लॉन टेनिस कोर्ट गईः 30 अपराह्न, उनके सामान्य समय के बजाय, अपीलार्थी-अभियुक्त से बचने के आदेश, जो शाम को अदालत जाते थे। जब दोनों लड़कियाँ लौटने वाली थीं, लगभग 6 बजेः30 पी.एम. मिस्टर पलटू-बॉल पिकर, कोर्ट से बाहर आए और सुश्री रुचिका को बताया कि अपीलकर्ता-आरोपी ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया था। हालाँकि, सुश्री रुचिका ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और सुश्री आराधना को बताया कि चूंकि उन्होंने अपने माता-पिता को 12.08.1990 पर अपीलार्थी-अभियुक्त के दुर्व्यवहार के बारे में सूचित नहीं किया था, इसलिए अपीलार्थी-अभियुक्त साहस महसूस कर रहा था और उससे छेड़छाड़ करने के उद्देश्य से उसे फिर से अपने कार्यालय में बुलाया

था। इसके बाद, दोनों ने अपने-अपने माता-पिता को 12.08.1990 पर हुई घटना का खुलासा करने का फैसला किया।तदनुसार, रुचिका ने अपीलार्थी-अभियुक्त के हाथों अपने साथ हुई छेड़छाड़ की घटना अपने पिता श्री एस. सी. गिरहोत्रा को सुनाई। साथ ही, सुश्री आराधना के माता-पिता को पूरी घटना से अवगत कराया गया।

(ज) यह सुनकर, श्री एस. सी. गिरहोत्रा ने इलाके के निवासियों को इकट्ठा किया, जो ज्यादातर प्रशिक्षु लड़कों और लड़कियों के माता-पिता थे, और वे अपीलार्थी-अभियुक्त से मिलने के लिए एच.एल.टी.ए. कार्यालय गए, लेकिन उन्हें सूचित किया गया कि अपीलार्थी-अभियुक्त पहले ही चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके थे। आई. डी. 1 पर सुश्री रुचिका, सुश्री आराधना, श्री आनंद प्रकाश और सुश्री आराधना के पिता और माँ सुश्री मधु प्रकाश द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक ज्ञापन/याचिका तत्कालीन सचिव (गृह), हरियाणा को प्रस्तुत की गई। गृह मंत्री श्री आर.आर. सिंह की मंजूरी के बाद तत्कालीन डी.जी.पी. को ज्ञापन/याचिका में अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था।

(i) घटना की जाँच करने के बाद, श्री आर.आर. सिंह ने निष्कर्ष निकाला कि छेड़छाड़ का आरोप सही तथ्यों पर आधारित है और अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') के प्रावधानों के तहत एक संज्ञेय मामला बनाया गया है और अपनी जाँच रिपोर्ट दिनांक 03.09.1990 को सचिव (गृह), हरियाणा सरकार को भेज दी।

(जे) जाँच के दौरान यह भी पता चला कि छेड़छाड़ की घटना के बाद सुश्री रुचिका ने खुद को अपने घर में बंद कर लिया। बाद में, 28.12.1993

पर, उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और 29.12.1993 पर उसकी मृत्यु हो गई।

(के) श्री आर. आर. सिंह की जांच रिपोर्ट की हरियाणा सरकार के कानूनी प्रभाग द्वारा 1990 और 1992 में जांच की गई थी, जिसमें अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी सिफारिश की गई थी। मधु प्रकाश-शिकायतकर्ता/ प्रतिवादी संख्या 2 ने हरियाणा सरकार में कई अधिकारियों से केस दर्ज करने का अनुरोध किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष 1997 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 1694 दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक आई. डी. 1 के आदेश के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, पंचकूला को निर्देश जारी किया कि मामला दर्ज होने के बाद, जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) को सौंप दी जाएगी और यह डी.आई.जी. के पुलिस थाना से कम के अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। इस न्यायालय ने अपने दिनांक आई. डी. 1 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के दिनांक आई. डी. 2 के आदेश को बरकरार रखा, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ भा.दं.सं. सी. की धारा 354 और 509 के तहत 1999 की संख्या 516 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) दर्ज की गई।

(i) सी. बी. आई. ने आई. पी. सी. की खंड 354 के तहत विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी. बी. आई., अंबाला की अदालत के समक्ष दिनांक 16.11.2000 का आरोप-पत्र दायर किया। आपराधिक प्रक्रिया भा.दं.सं., 1973 (संक्षेप में 'भा.दं.सं.') की खंड 473 के तहत सीबीआई द्वारा आरोप-पत्र दाखिल करने में देरी को माफ करने और संज्ञान लेने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, जिसे विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अपने दिनांक 1 के

आदेश द्वारा अनुमति दी थी। दिनांक 1 के आदेश से व्यथित होने के कारण, अपीलार्थी-अभियुक्त ने विलंब की क्षमा को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष 2000 की सं. 46381 रिट याचिका (आपराधिक) को प्राथमिकता दी। उच्च निचली अदालत ने अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा निचली अदालत को मामले को अधिमानतः छह महीने के भीतर निपटाने के निर्देश के साथ याचिका को खारिज कर दिया।

(एम) इसके अलावा, आरोप पत्र में भा.दं.सं. सी. की खंड 376 को जोड़ने के लिए एक याचिका दायर की गई थी जिसे निचली अदालत के दिनांक 23.10.2001 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। दिनांकित 23.10.2001 आदेश से व्यथित होने के कारण, अपीलार्थी-अभियुक्त ने क्रिमिनल मिस्क को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या 44607-एम/2011 है। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 12.02.2002 के आदेश द्वारा, निचली अदालत द्वारा पारित दिनांक 23.10.2001 के आदेश को रद्द कर दिया। अपील में, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.02.2002 के आदेश को भी बरकरार रखा।

(एन) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ की अदालत ने अपने फैसले और आदेश दिनांक 21.12.2009 द्वारा चालान संख्या 3/17-11-2000,12 टी/10.04.2006 आरबीटी 191/17-11-2009 में अपीलार्थी-आरोपी को भा.दं.सं. की खंड 354 के तहत अपराध का दोषी ठहराया और उसे छह महीने के लिए कठोर कारावास (आर. आई.) और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 1,000/- आई. डी. 1 दिनांकित निर्णय और आदेश से व्यथित होने के कारण, अपीलार्थी-अभियुक्त ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ के न्यायालय के समक्ष आई. डी. 2 की सं. 5 होने के कारण दाण्डिक अपीलीय को प्राथमिकता

दी। सी. बी. आई. और मधु प्रकाश-प्रतिवादी संख्या 2 ने भी सजा बढ़ाने के लिए अदालत के समक्ष दाण्डिक अपीलीय को क्रमशः 12.01.2010 की संख्या 26 और 05.02.2010 की संख्या 22 होने को प्राथमिकता दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ ने अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जबकि सी. बी. आई. और मधु प्रकाश द्वारा सजा की अपर्याप्तता और कारावास की सजा बढ़ाने के लिए दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया और अपीलार्थी-अभियुक्त को भा.दं.सं. सी. की खंड 354 के तहत अपराध करने के लिए 1 प्रतिशत (डेढ़) के कठोर कारावास से सम्मानित किया गया। जुर्माने की सजा अपरिवर्तित रही।

(0) दिनांक 1 के निर्णय और आदेश से व्यथित होने के कारण, अपीलार्थी-अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2010 की सं. 1558 के आपराधिक संशोधन को प्राथमिकता दी।उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 01.09.2010 के आदेश द्वारा अपीलार्थी- अभियुक्त द्वारा दायर संशोधन को खारिज कर दिया।

(पी) उपरोक्त आदेश से व्यथित, अपीलार्थी-अभियुक्त ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से इस याचिका को प्राथमिकता दी है। इस न्यायालय ने अपने दिनांक 11.11.2010 के आदेश द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा जमानत के लिए दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है।

3. अपीलार्थी-अभियुक्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन और सी. बी. आई. की विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री विभा दत्ता मखीजा और प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान सहायक श्री विकास मेहता को सुना।

प्रतिद्वंद्वी विवादः

4. अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एच. एल. टी. ए. की स्थिति को देखते हुए श्रमिकों सहित कई लोगों की उपस्थिति के साथ प्रासंगिक समय पर एक गैराज में शिफ्ट कार्यालय बनाना, इस तरह के कार्य के लिए प्रयास करना भी असंभव होगा, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि इस कार्य को अन्य लोग भी देख सकते हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की कहानी आत्यन्तिक रूप झूठी और तुच्छ है और अपीलकर्ता- अभियुक्त को वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता पक्ष और राज्य के उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा एक गुप्त उद्देश्य के साथ फंसाया गया है। अपीलार्थी-अभियुक्त न तो श्री एस. सी. गिरहोत्रा के घर गया और न ही एच. एल. टी. ए. कार्यालय में रुचिका के साथ आई. डी. 1 पर मिलने के लिए कहा। यह भी तर्क दिया गया कि हरियाणा राज्य के कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित कई इच्छुक व्यक्तियों द्वारा लंबे समय तक विचार-विमर्श और विचार-विमर्श के बाद ज्ञापन/याचिका का मसौदा तैयार किया गया है। कथित रूप से संबंधित समय पर रुचिका के साथ जाने वाले खिलाड़ियों के नाम का ज्ञापन में जानबूझकर उल्लेख नहीं किया गया है और बाद में सुश्री आराधना को 'साथी खिलाड़ी' के रूप में लगाया गया है। यह तर्क दिया गया था कि पसंद के चश्मदीद गवाह को पेश करने के उद्देश्य से ज्ञापन में 'साथी खिलाड़ी' शब्दों का उल्लेख किया गया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि कथित ज्ञापन पर सुश्री रुचिका के हस्ताक्षर झूठे और जाली हैं और इस आधार पर दस्तावेज़ पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह दस्तावेज़ घटना के विवरण का खुलासा नहीं करता है और केवल यह सुझाव देता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने सुश्री रुचिका के साथ दुर्व्यवहार किया जो भा.दं.सं. सी. की खंड 354 को आकर्षित नहीं करता है।

5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि सुश्री रुचिका या उनके

पिता श्री एस. सी. गिरहोत्रा या श्री आशु-सुश्री रुचिका के बड़े भाई या श्रीमती मधु प्रकाश (पीडब्लू-2) या श्री द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। पुलिस थाने में आनंद प्रकाश (पीडब्लू-1) या सुश्री आराधना (पीडब्लू-13) द्वारा। आईडी1 के बाद भी, जब सुश्री रुचिका और सुश्री आराधना ने कथित तौर पर अपने माता-पिता को सूचित किया, तो उनमें से किसी ने भी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पुलिस से संपर्क नहीं किया, पुलिस चौकी, सेक्टर 6, पंचकूला टेनिस कोर्ट से केवल 300 गज की दूरी पर है। यह श्री एस. सी. गिरहोत्रा के घर के बहुत पास स्थित है। इस तरह अनुचित और अस्पष्टीकृत देरी के परिणामस्वरूप जोड़-तोड़ की गई और अदालत के समक्ष उचित संस्करण नहीं रखा जा सका।

6. अपीलार्थी-अभियुक्त के वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि श्री आर. आर. सिंह द्वारा की गई जांच अधिकार क्षेत्र के बिना थी क्योंकि अपीलार्थी-अभियुक्त, प्रासंगिक समय पर, बी. बी. एम. बी. के साथ प्रतिनियुक्ति पर था और हरियाणा सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं था।उन्होंने आगे तर्क दिया कि हरियाणा सरकार में आई. ए. एस. लॉबी पूरी तरह से अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ थी और उसने अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ श्री आनंद प्रकाश (पी. डब्ल्यू.-1) और अन्य लोगों के साथ सांठगांठ की थी।उन्होंने आगे बताया कि दो टेनिस संघों के बीच प्रतिद्वंद्विता थी, एक अपीलार्थी-आरोपी के नेतृत्व में और एक बाद में आईएएस समूह द्वारा सचिव (गृह) श्री जे. के. दुग्गल के साथ श्री बी. एस. ओझा के संरक्षण में इसके अध्यक्ष के रूप में गठित किया गया था। अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से आगे यह तर्क दिया गया कि हरियाणा टेनिस संघ (एच. टी. ए.) के गठन से पहले, आई. ए. एस. लॉबी ने अपीलार्थी-अभियुक्त पर श्री बी. एस. ओझा के पक्ष में एच. एल. टी. ए. के अध्यक्ष पद से हटने का दबाव डाला, जिस पर अपीलार्थी-अभियुक्त ने इनकार कर दिया, जिससे श्री बी. एस. ओझा नाराज हो गए, जिनके पास श्री आर. आर. सिंह द्वारा जांच का आदेश देने के

लिए मजबूत कारण थे और उनके अधीन काम करने वाले पुलिस अधिकारियों ने अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ उक्त ज्ञापन का मसौदा तैयार किया था। श्री आर. आर. सिंह द्वारा की गई जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके खिलाफ कोई जांच नहीं की जा सकी और न ही उन्होंने उचित तरीके से जांच की है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया कि मीडिया ने वर्तमान मामले में नकारात्मक भूमिका निभाई है और केवल शिकायतकर्ता पक्ष के साथ मिलीभगत में चुनिंदा समाचारों को प्रकाशित किया है। बॉल पिकर-पाल्टू और कोच-के. टी. थॉमस जैसे मौखिक गवाह, जो कथित रूप से गुप्त घटना के स्थान पर मौजूद थे, से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है। इसके अलावा, गवाहों ने बहुत सुधार किए हैं और गवाहों के बयानों में अन्य विसंगतियां भी हैं और इसलिए, नीचे दी गई अदालतों द्वारा उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अंततः तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला झूठा और तुच्छ है, जिसका शुद्ध परिणाम यह है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा है और अपीलार्थी-अभियुक्त बरी होने का हकदार है।

7. इसके विपरीत, सी. बी. आई. के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कहा कि यह घटना सुश्री आराधना (पी. डब्ल्यू.-13) की निर्दोष गवाही से अच्छी तरह से साबित होती है।प्रत्यक्षदर्शी अंत तक अपनी गवाही के साथ खड़ी रही और इसलिए, उपरोक्त साक्ष्य के संबंध में अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से आग्रह किए गए तर्क की कोई प्रासंगिकता या सार नहीं है।पीडब्लू-13 के बयान की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत आसान हो सकता है कि इस बात की पूरी संभावना थी कि सुश्री रुचिका को याचिकाकर्ता-अभियुक्त द्वारा उस तरीके से गले लगाया जा सकता था जैसा कि चश्मदीद गवाह ने अंततः निचली निचली अदालत के समक्ष अपने बयान में वर्णित किया था।यहां तक कि सुश्री रुचिका के पिता श्री एस. सी. गिरहोत्रा ने भी स्पष्ट रूप से

बयान दिया है कि अपीलकर्ता-अभियुक्त उनसे मिला और उनसे अपनी बेटी को विदेश नहीं भेजने का अनुरोध किया और 12.08.1990 पर अपने कार्यालय में उनसे मिलने पर भी जोर दिया, जिसकी पुष्टि पीडब्लू-13 के बयान से होती है कि दोनों लड़कियां एचएलटीए में अपीलकर्ता-अभियुक्त से मिलने उनके कार्यालय गई थीं।

8. ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दावे के साथ-साथ एस. एच. ओ. को दिए गए आवेदन पर, सी. बी. आई. के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत किया कि जहां तक दस्तावेज़ पर सुश्री रुचिका के हस्ताक्षर का संबंध है, सुश्री रुचिका ने अन्य लोगों की उपस्थिति में कथित ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यह सुश्री आराधना, श्रीमती मधु प्रकाश और श्री जैसे गवाहों द्वारा स्थापित किया गया है। आनंद प्रकाश जिनकी उपस्थिति में उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जो एक सीधा सबूत है।विशेषज्ञ गवाह के साक्ष्य को आरोप का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता है और इसकी पुष्टि के लिए स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्य की आवश्यकता होती है।उसने आगे प्रस्तुत किया कि सुश्री रुचिका अपने हस्ताक्षरों की वास्तविकता के बारे में गवाही देने के लिए सबसे अच्छी व्यक्ति थीं, लेकिन चूंकि वह अब नहीं हैं, इसलिए वह कथित ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर की वास्तविकता के बारे में गवाही देने के लिए गवाह बॉक्स में उपस्थित नहीं हो सकीं।उनकी अभावि में, जिन व्यक्तियों की उपस्थिति में उन्होंने दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए, वे पीड़ित के हस्ताक्षर की वास्तविकता को साबित करने के लिए सबसे अच्छे गवाह हैं।अभिलेख पर मजबूत प्रत्यक्ष साक्ष्य का खंडन हस्तलेखन विशेषज्ञ के कमजोर प्रकार के साक्ष्य द्वारा नहीं किया जा सकता है, जिस पर अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील द्वारा भरोसा किया जाता है।

9. अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा आग्रह किए गए तर्क के संबंध में कि सुश्री आराधना 'साथी खिलाड़ी' थीं?जैसा कि ज्ञापन में उल्लेख किया गया है, जिसके आधार

पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उसमें हेरफेर किया गया था, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत किया कि ज्ञापन की सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि यह केवल उन घटनाओं का एक क्रम देता है जो शुरू से ही हुई थीं और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई हेरफेर नहीं किया गया था।केवल इस आधार पर कि तत्कालीन डी. आई. जी. श्री सी. पी. बंसल और तत्कालीन डी. एस. पी. श्री शाम लाल गोयल मौके पर मौजूद थे, यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने इसके मसौदे में सक्रिय रूप से भाग लिया और इसमें कुछ अनावश्यक और अनुचित तथ्य जोड़े गए।यदि अनुभवी पुलिस अधिकारियों ने इसके मसौदे में भाग लिया होता तो इसे-प्राथमिकी आर. के रूप में होना चाहिए था और सबूत को इसमें विशेष रूप से इंगित किया जाना चाहिए था।लेकिन ज्ञापन की भाषा ऐसी है कि लोगों ने कथित कृत्य के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाने की कोशिश की है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।ज्ञापन में सुश्री आराधना के नाम का उल्लेख नहीं करने का कारण यह है कि उसे आरोपी द्वारा परेशान किया जा सकता था, जो एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी है।यही कारण है कि सुश्री रुचिका या सुश्री आराधना या उनके माता-पिता ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्थानीय पुलिस से संपर्क नहीं किया। वे इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि अपीलार्थी-अभियुक्त, राज्य में एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के नाते, निश्चित रूप से जांच में बाधा डालेगा या पुलिस अधिकारियों को शिकायतकर्ता पक्ष के साथ सहयोग करने की अनुमति नहीं देगा।

10. सी. बी. आई. के वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे बताया कि श्री आर. आर. सिंह ज्ञापन के तथ्यों की जांच करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम अधिकारी थे और उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा ज्ञापन में दिए गए तथ्यों की जांच करने और उसे एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।किसी व्यक्ति को जाँच करने के लिए अधिनियमी रूप से सक्षम प्राधिकारी बनाने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि उसके पास ऐसा

अधिकार हो जो किसी क़ानून से निकलता हो।यह पर्याप्त है कि ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा तथ्य की जांच करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत किया गया था।इस प्रकार, एस. आर. आर. सिंह विचाराधीन तथ्यों की जांच करने के लिए सक्षम अधिकारी थे और उनके सामने गवाहों द्वारा दिए गए बयान साक्ष्य में स्वीकार्य हैं, चाहे घटनाएँ होने के समय और बयान दिए जाने की तारीख के बीच का समय अंतराल कुछ भी हो।

11. सी. बी. आई. के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अंततः प्रस्तुत किया कि एच. एल. टी. ए. और एच. टी. ए. के बीच कथित प्रतिद्वंद्विता के साथ-साथ श्री आनंद प्रकाश (पी. डब्ल्यू.-1) और श्री एस. सी. गिरहोत्रा (पी. डब्ल्यू.-15) की विश्वसनीयता के बारे में अपीलकर्ता-अभियुक्त के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों का मामले पर कोई असर नहीं है और अभियोजन पक्ष ने भा.दं.सं. सी. की खंड 354 के तहत अपीलकर्ता-अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए मामला बनाया है।

चर्चाः

12. यह विवादित नहीं है कि एच. एल. टी. ए. हरियाणा के पंचकुला में 1988-89 में शुरू किया गया था।अपीलार्थी-अभियुक्त एच. एल. टी. ए. का अध्यक्ष था। इसका कार्यालय पंचकूला के सेक्टर 6 में एक निर्माणाधीन घर के गैराज में स्थापित किया गया था, जिसका स्वामित्व अपीलार्थी-अभियुक्त के पास था।यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि सुश्री आराधना (पीडब्लू-13), श्री मनीष अरोड़ा (पीडब्लू-3), श्री विपुल चनाना (पीडब्लू-4) और सुश्री रुचिका (मृत होने के बाद से) एसोसिएशन के सदस्य थे और इसके कोर्ट में टेनिस खेलते थे।अभियोजन पक्ष का मामला है कि आई. डी. 1 पर, अपीलार्थी-अभियुक्त श्री एस. सी. गिरहोत्रा (पी. डब्ल्यू.-15) के घर गया और उससे अनुरोध किया कि वह अपनी बेटी को कोचिंग के लिए कनाडा न भेजे क्योंकि वह उसके लिए एच. एल. टी. ए. में ही विशेष कोचिंग की व्यवस्था करेगा।श्री एस. सी. गिरहोत्रा

(पीडब्लू-15) ने अपने बयान में इस तथ्य को अच्छी तरह से साबित किया है।उसने निचली अदालत के समक्ष गवाही दी है कि आई. डी. 1 पर, अपीलार्थी-अभियुक्त दोपहर लगभग आई. डी. 2 पर उसके घर गया था और उसे अपनी बेटी को कनाडा नहीं भेजने के लिए कहा था और वह उसके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा।अपीलार्थी-अभियुक्त ने आगे उसे प्रशिक्षण के बारे में चर्चा करने के लिए अपनी बेटी को 12.08.1990 पर, लगभग 12.00 दोपहर में, अपने कार्यालय में भेजने के लिए कहा। उस समय सुश्री रुचिका अपने घर पर मौजूद नहीं थीं।उसकी वापसी पर, पीडब्लू-15 ने उसे इसकी सूचना दी और उसे अपीलार्थी-अभियुक्त से उसके कार्यालय में दोपहर में 12.08.1990 पर मिलने के लिए भी कहा।इस तथ्य की पुष्टि सुश्री आराधना (पीडब्लू-13) के बयान से होती है।उसने गवाही दी है कि 12.08.1990 पर, लगभग 11.00 सुबह, सुश्री रुचिका उसके घर आई और उसने बहुत उत्साह से उसे बताया कि 11.08.1990 पर, अपीलकर्ता-आरोपी उसके घर गया था और उसके पिता से अनुरोध किया था कि वह उसे विदेश न भेजे और वह उसके लिए HLTA में ही विशेष कोचिंग की व्यवस्था करेगा क्योंकि वह एक होनहार खिलाड़ी थी।उसने सुश्री आराधना को आगे सूचित किया कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने उसे एच. एल. टी. ए. कार्यालय में दोपहर में 12.08.1990 पर उससे मिलने के लिए कहा था।यही तथ्य ज्ञापन में भी मिलता है जिस पर सुश्री रुचिका ने अन्य लोगों के साथ हस्ताक्षर किए थे।पीडब्लू-15 का साक्ष्य पीडब्लू-13 के साक्ष्य की पुष्टि आदेशता है ताकि इस तथ्य की पुष्टि की जा सके कि अपीलार्थी-अभियुक्त श्री एस. सी. गिरहोत्रा के घर 11.08.1990 पर गया था और उसे सुश्री रुचिका को 12.08.1990 पर, दोपहर 12.00 पर अपने कार्यालय भेजने के लिए कहा था।

13. सुश्री रुचिका (मृत होने के बाद से) और सुश्री आराधना 12.08.1990 पर लॉन टेनिस कोर्ट में खेलने गई थीं और जब वे श्री खेल रहे थे। पलटू-गेंद उठाने वाला

वहाँ आया और सुश्री रुचिका को बताया कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने उसे दोपहर में अपने कार्यालय में बुलाया था।तदनुसार, सुश्री रुचिका और सुश्री आराधना उनके कार्यालय गईं। अपीलार्थी-अभियुक्त ने सुश्री आराधना को प्रशिक्षक श्री टी. थॉमस को लाने के लिए कहा।जब सुश्री आराधना वहाँ से चली गई थी, अपीलार्थी-अभियुक्त ने सुश्री रुचिका की विनम्रता से छेड़छाड़/नाराजगी जताई।जब सुश्री आराधना कार्यालय लौटी, तो उसने अपीलार्थी-अभियुक्त को सुश्री रुचिका के साथ छेड़छाड़ करते देखा।सुश्री आराधना ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से उस दिन पदच्युत किया है जब वे दोनों आई-ई थे।, सुश्री रुचिका और सुश्री आराधना टेनिस खेल रहे थे, श्री पलटू, बॉल पिकर, आए और सुश्री रुचिका को सूचित किया कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने उन्हें एच. एल. टी. ए. कार्यालय में बुलाया था।उन्होंने देखा कि अपीलार्थी-अभियुक्त अपने कार्यालय के बाहर खड़ा था।उन्हें देखकर, अपीलार्थी-अभियुक्त ने उन्हें अपने कार्यालय आने के लिए कहा।यद्यपि सुश्री रुचिका ने अपीलार्थी-अभियुक्त से कार्यालय के बाहर उससे बात करने का अनुरोध किया, लेकिन उसने उन्हें अपने कार्यालय आने के लिए जोर दिया।उनके आग्रह पर, उन्होंने उनके कार्यालय की ओर उनका पीछा किया।अभियुक्त द्वारा पूछे जाने पर, एक कुर्सी लाई गई जिस पर सुश्री आराधना (पीडब्लू-13) बैठ गईं जबकि रुचिका अपनी दाहिनी ओर खड़ी रही।इसके तुरंत बाद, अपीलार्थी-अभियुक्त ने सुश्री आराधना को प्रशिक्षक श्री टी. थॉमस को लाने के लिए कहा।जब वह कोच को बुलाने के लिए बाहर गई, तो उसने उसे सड़क के पार घर के दूसरी तरफ कुछ दूरी पर खड़ा पाया।उसने गेंद उठाने वाले पलटू को जाकर कोच को लाने के लिए कहा।श्री थॉमस, श्री पलटू द्वारा इसके बारे में सूचित किए जाने पर, उस समय आने में असमर्थता व्यक्त करते हुए सुश्री आराधना की ओर अपना हाथ हिलाया।इसके बाद, सुश्री आराधना लौट आईं और जब उन्होंने कार्यालय में प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा कि अपीलकर्ता-अभियुक्त ने सुश्री रुचिका का एक हाथ पकड़ा हुआ था और उसका दूसरा हाथ उनकी कमर में था।सुश्री

रुचिका अपने दूसरे हाथ से उसे दूर धकेलकर खुद को रिहा करने की बहुत कोशिश कर रही थी।सुश्री आराधना (पीडब्लू-13) को देखकर, अपीलार्थी-अभियुक्त घबरा गया और सुश्री रुचिका को छोड़ दिया और अपनी कुर्सी पर गिर गया।जब उसने अपीलार्थी-अभियुक्त को सूचित किया कि प्रशिक्षक ने उसके कार्यालय आने से इनकार कर दिया है, तो अपीलार्थी-अभियुक्त ने उसे फिर से जाने और प्रशिक्षक को व्यक्तिगत रूप से बुलाने का आदेश दिया।इस बीच सुश्री रुचिका उनके पास आईं और कार्यालय से बाहर चली गईं।जब पीडब्लू-13 उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा था, तो अपीलार्थी-आरोपी ने उससे कहा, "उसे शांत होने के लिए कहें, वह जो कहेगी मैं वही करूंगी।"इसके बाद, पीडब्लू-13 ने सुश्री रुचिका का पीछा किया और जब वह उनके पास पहुंची, तो रुचिका जोर से रोने लगी।जब उसने सुश्री रुचिका से पूछा कि क्या हुआ था, तो उसने बताया कि जैसे ही वह कोच को लाने के लिए निकली, अपीलकर्ता-अभियुक्त ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे वह बड़ी कठिनाई से छोड़ दिया गया, लेकिन उसने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से अपीलार्थी-अभियुक्त ने उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे गले लगा लिया।उसने उसे आगे बताया कि इस बीच जब पीडब्लू-13 वहाँ पहुँचा तो वह डर गया और तुरंत उसे छोड़ दिया।यह चर्चा करने के बाद कि घटना का खुलासा उनके माता-पिता को किया जाए या नहीं, दोनों ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में सूचित नहीं करने का फैसला किया क्योंकि अपीलकर्ता-आरोपी, एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी होने के नाते, उनके परिवारों को नुकसान पहुंचा सकता है।पीडब्लू-13 के बयान से अपीलार्थी-अभियुक्त के हाथों सुश्री रुचिका के साथ छेड़छाड़ बहुत अच्छी तरह से साबित होती है। सुश्री आराधना (पीडब्लू-13) के झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था।वास्तव में, उसने अपीलार्थी-अभियुक्त के हाथों सुश्री रुचिका के साथ छेड़छाड़ के वास्तविक कृत्य को देखा।इसके अलावा, अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा सुश्री रुचिका के साथ छेड़छाड़ के बारे में

तथ्य श्री आनंद प्रकाश (पीडब्लू-1), श्रीमती मधु प्रकाश (पीडब्लू-2), श्री मनीष अरोड़ा (पीडब्लू-3), श्री विपुल चानन (पीडब्लू-4) और श्री एस. सी. गिरहोत्रा (पीडब्लू-15) द्वारा शपथ पर बताया गया है।इस बात का कोई कारण नहीं है कि पीडब्लू-13 और उपरोक्त अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह अपीलार्थी-अभियुक्त को मामले में गलत तरीके से क्यों फंसाते हैं।

14. सुश्री रुचिका और सुश्री आराधना 4 बजे 14.08.1990 पर लॉन टेनिस कोर्ट गईं:30 अपराह्न, अपीलार्थी-अभियुक्त के साथ टआदेशाव से बचने के लिए जानबूझआदेश उनके सामान्य समय के बजाय, जो आमतौर पर प्रतिदिन शाम को अदालत जाते थे।शाम करीब 6:30 बजे, जब वे अभ्यास के बाद लौटने वाले थे, श्री पलटू-बॉल पिकर, लॉन टेनिस कोर्ट पर आए और सुश्री रुचिका को बताया कि अपीलार्थी-आरोपी ने उन्हें तुरंत अपने कार्यालय में बुलाया था।हालाँकि, सुश्री रुचिका ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया और सुश्री आराधना को बताया कि चूंकि उन्होंने अपने माता-पिता को उस घटना के बारे में सूचित नहीं किया था जो 12.08.1990 पर हुई थी, जिसने अपीलार्थी-अभियुक्त को प्रोत्साहित किया है।इसके बाद, उन्होंने अपीलार्थी-अभियुक्त के खुलेआम किए गए कृत्य के बारे में अपने माता-पिता को सूचित करने का फैसला किया।वे सुश्री रुचिका के घर गए जहाँ वे सुश्री रुचिका के पिता श्री एस. सी. गिरहोत्रा से मिले।सुश्री रुचिका ने अपने पिता को छेड़छाड़ की घटना सुनानी शुरू कर दी, हालांकि, वह पूरी घटना नहीं बता सकी और रो पड़ी, जिसके बाद उसके पिता ने सुश्री आराधना को सुश्री रुचिका को उसकी माँ के पास ले जाने के लिए कहा।वे सुश्री आराधना के घर गए जहाँ श्रीमती मधु प्रकाश (पीडब्लू-2) और श्री आनंद प्रकाश (पीडब्लू-1) उपस्थित थे।सुश्री रुचिका ने पूरी घटना का खुलासा पीडब्लू-2 को किया, जिसने आगे अपने पति को उक्त घटना के बारे में सूचित किया।इसके बाद, सुश्री रुचिका, सुश्री आराधना, श्री आनंद प्रकाश, श्रीमती मधु प्रकाश और श्री एस. सी.

गिरहोत्रा और अन्य व्यक्ति अपीलार्थी-अभियुक्त से मिलने के लिए एच. एल. टी. ए. अदालत गए, जहाँ से उन्हें पता चला कि अपीलार्थी-अभियुक्त पहले ही चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुका है।

15. 15.08.1990 पर, कई व्यक्ति, जो ज्यादातर खिलाड़ी और उनके माता-पिता थे, श्री आनंद प्रकाश के आवास पर एकत्र हुए।उन्होंने निर्णय लिया कि इस घटना को हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। तदनुसार, एक ज्ञापन तैयार किया गया।विभिन्न प्राधिकरणों को सौंपने के लिए इस ज्ञापन की कई प्रतियां तैयार की गईं।इस ज्ञापन पर श्री ने हस्ताक्षर किए थे। आनंद प्रकाश, सुश्री रुचिका, श्रीमती मधु प्रकाश, मीनू, संगीत, आराधना, अनिरुद्ध, बीनू, नरेश मित्तल, सी. एस. गुप्ता और श्री आई. डी. मित्तल।अदालत में जिन गवाहों से पूछताछ की गई, उन्होंने ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर के साथ-साथ सुश्री रुचिका के हस्ताक्षर की पहचान की।अपीलार्थी-अभियुक्त ने सुश्री रुचिका के हस्ताक्षरों की वास्तविकता पर विवाद किया।उन्होंने हस्तलेखन विशेषज्ञ की जांच करके अपने तर्क को साबित करने की कोशिश की।अपीलार्थी-अभियुक्त का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि जिन गवाहों से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ की गई है और जिनकी उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, उन्होंने सुश्री रुचिका के हस्ताक्षरों की पहचान की है।श्री आनंद प्रकाश ने ज्ञापन की तैयारी को सिद्ध कर दिखाया है।इस संबंध में, कानून बहुत स्पष्ट है कि एक तथ्य है।सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए।गवाहों ने ज्ञापन पर सुश्री रुचिका के हस्ताक्षरों की पहचान की थी, इसलिए, हस्तलेखन विशेषज्ञ के साक्ष्य को सुरक्षित नहीं माना जा सकता है और इसके लिए स्वतंत्र गवाहों से पुष्टि की आवश्यकता होती है।जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, सुश्री रुचिका के हस्ताक्षर उन गवाहों द्वारा साबित किए गए हैं जिन्होंने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और मामले में प्रत्यक्ष, प्राथमिक और सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य हैं और इसलिए, उन पर भरोसा किया

जा सकता है।

16. आई. डी. 1 पर तत्कालीन सचिव (गृह) श्री जे. के. दुग्गल (पीडब्लू-12) को ज्ञापन दिया गया, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी।उन्होंने जिन लोगों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा था, उन्हें लॉन टेनिस कोर्ट पहुंचने के लिए कहा, जहां तत्कालीन एस. डी. एम. श्री एस. के. जोशी भी पहुंचेंगे।वहाँ पहुँचने के बाद, उन्हें नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित 13.08.1990 से सुश्री रुचिका के निलंबन की घोषणा करने वाला 15.08.1990 दिनांकित एक नोटिस मिलाःतत्कालीन एस. डी. एम. श्री एस. के. जोशी भी वहाँ पहुँचे।श्री कुलदिप सिंह-प्रबंधक और श्री टी. थॉमस-प्रशिक्षक भी वहाँ उपस्थित थे।गवाहों की उपस्थिति में पूछे जाने पर श्री कुलदिप सिंह ने बताया कि उन्होंने अपीलार्थी-अभियुक्त के निर्देश पर नोटिस चिपकाया है।उन्होंने आगे खुलासा किया कि सुश्री रुचिका ने अनुशासनहीनता का कोई कार्य नहीं किया है।यह पूछे जाने पर, श्री कुलदिप सिंह ने नोटिस पर लिखित रूप में वही तथ्य दिए।इस तथ्य की पुष्टि कोच-श्री टी. थॉमस ने की और उन्होंने एक ऐसे बिंदु पर हस्ताक्षर किए जहां निम्नलिखित शब्द लिखे गए थे "मैं श्री के समर्थन की सामग्री का समर्थन करता हूं। कुलदिप सिंह "।यदि सुश्री रुचिका द्वारा अनुशासनहीनता का कोई कार्य किया गया है तो उन्हें इसे लिखित रूप में देने के लिए भी कहा गया था।इस पर, उन्होंने इस प्रभाव का समर्थन किया कि उनकी जानकारी के अनुसार सुश्री रुचिका ने एच. एल. टी. ए. टेनिस कोर्ट में दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता का कोई कार्य नहीं किया है।यह नोटिस श्री आनंद प्रकाश ने निचली निचली अदालत के समक्ष अपने बयान के समय पेश किया था।उनके साक्ष्य में यह भी आया है कि एस. डी. एम. द्वारा समर्थन करने के तुरंत बाद उन्हें नोटिस दिया गया था।इन तथ्यों को पीडब्लू-1, पीडब्लू-2, पीडब्लू-3, पीडब्लू-4, पीडब्लू-5 और पीडब्लू-13 द्वारा साबित किया गया है।उस दिन और समय पर श्री कुलदिप सिंह और श्री टी. थॉमस की उपस्थिति पंचकूला के तत्कालीन एस. एच. ओ. द्वारा पहले ही साबित की

जा चुकी है, जो उस तारीख को गश्त पर थे और घटना के बारे में मौखिक संदेश प्राप्त करने पर मौके पर पहुंचे थे।

17. श्री आर. आर. सिंह को हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने ज्ञापन में निहित आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था।उक्त आदेश के अनुपालन में, श्री आर. आर. सिंह ने श्रीमती मधु प्रकाश (पीडब्लू-2), सुश्री आराधना (पीडब्लू-13), श्री एस. सी. गिरहोत्रा (पीडब्लू-15) और श्री अनिल कुमार सहित गवाहों के बयान दर्ज किए।सुश्री रुचिका और श्री आनंद प्रकाश (पीडब्लू-1) के बयान भी दर्ज किए गए।जाँच के बाद, उन्होंने सिफारिश की कि भा.दं.सं. सी. के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाए।इस तथ्य के बावजूद कि श्री आर. आर. सिंह ने अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी, राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।यह सबसे आश्चर्य की बात है कि उक्त रिपोर्ट और इतने उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी यानी पुलिस महानिदेशक, हरियाणा द्वारा की गई सिफारिशों को कोई महत्व नहीं दिया गया।

18. अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि श्री बी. एस. ओझा और श्री जे. के. दुग्गल को उनके खिलाफ बहुत शिकायत थी।यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी-अभियुक्त और श्री आर. आर. सिंह के बीच संबंध 1976 से तनावपूर्ण थे।लेकिन अदालत में पेश होते समय गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया।सी. बी. आई. के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दृढ़ता से कहा है कि श्री आर. आर. सिंह द्वारा एक उचित रिपोर्ट दी गई थी और यह आम अनुभव की बात है कि कोई भी लड़की या पिता अपने दुश्मन के खिलाफ भी इस तरह की जघन्य प्रकृति की झूठी शिकायत नहीं करेगा।

19. श्री आर. आर. सिंह ने हरियाणा सरकार के आदेश के तहत जांच की थी,

इसलिए वे ज्ञापन में लगाए गए आरोपों की जांच/जांच करने में सक्षम थे।इस प्रकार, उनके द्वारा दर्ज किए गए सभी बयान पुष्टि के उद्देश्य से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की खंड 157 के तहत स्वीकार्य हैं।श्री जे. के. दुग्गल और श्री बी. एस. ओझा स्वतंत्र गवाह हैं और उन्हें अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है जैसा कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आरोप लगाया है।तर्कों के लिए, भले ही यह सही माना जाए कि उनके बीच एच. एल. टी. ए. के नियंत्रण को लेकर कुछ विवाद था, लेकिन यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जो उन्हें अपीलार्थी-अभियुक्त को गलत तरीके से फंसाने के लिए प्रेरित करता।इन आरोपों की पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि इन दोनों अधिकारियों ने किसी भी तरह से ज्ञापन तैयार करने या मामले में अपीलार्थी-अभियुक्त को फंसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।श्री आनंद प्रकाश (पीडब्लू-1) और श्री एस. सी., गिरहोत्रा (पीडब्लू-15) के साथ इन दोनों अधिकारियों के किसी भी सांठगांठ का सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है।अपीलार्थी-अभियुक्त और पीडब्लू-1 के बीच किसी मनगढ़ंत मामले में उसे फंसाने के लिए किसी भी शत्रुता का सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है।यह अपीलार्थी-अभियुक्त का मामला है कि श्री आर. आर. सिंह द्वारा दर्ज किए गए बयान का उपयोग अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य अधिनियम की खंड 157 के तहत पुष्टि के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त का तर्क बिल्कुल भी मान्य नहीं है।इस खंड में गवाहों के बयानों की दो श्रेणियों की परिकल्पना की गई है, जिनका उपयोग पुष्टि के लिए किया जा सकता है। सबसे पहले एक गवाह द्वारा किसी भी व्यक्ति को उस समय या उसके बारे में दिया गया बयान है जब घटना हुई थी।दूसरा उनके द्वारा मामले की जांच करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम किसी भी प्राधिकारी को दिया गया बयान है।इस तरह के बयान स्वीकार करने योग्य होते हैं, चाहे वे घटना के लंबे समय बाद दिए गए हों।लेकिन अगर बयान गैर-प्राधिकारी को दिया गया था, तो समय बीतने के कारण यह अपना संभावित

मूल्य खो देता है।श्री आर. आर. सिंह घटना की जाँच करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम अधिकारी थे।राज्य सरकार ने उन्हें ज्ञापन में दिए गए तथ्यों की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए कहा था।किसी व्यक्ति को जाँच करने के लिए अधिनियमी रूप से सक्षम प्राधिकारी बनाने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि उसके पास ऐसा अधिकार हो जो किसी क़ानून से निकलता हो।यह पर्याप्त है कि ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा मामले की जांच करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत किया गया था। इसलिए, हमारा विचार है कि श्री आर. आर. सिंह विचाराधीन तथ्य की जांच करने के लिए सक्षम अधिकारी थे और उनके सामने गवाहों द्वारा दिए गए बयान साक्ष्य में स्वीकार्य हैं, चाहे घटनाएँ होने के समय और बयान दिए जाने की तारीख के बीच का समय अंतराल कुछ भी हो।श्री आर. आर. सिंह वास्तव में मामले की जांच करने के लिए सक्षम थे क्योंकि उनके द्वारा की गई जांच केवल एक तथ्य खोजने वाली जांच थी।निर्विवाद तथ्य यह है कि श्री आर. आर. सिंह द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।इसके अलावा, श्री सहित सभी गवाह। अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए जे. के. दुग्गल और श्री बी. एस. ओझा स्वतंत्र गवाह हैं और अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा सुझाए गए शत्रुता, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, साबित नहीं होती है।

20. अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वर्तमान तथ्य स्थिति में, कैसे एक व्यक्ति मेज के पीछे खड़े होकर दूसरे को गले लगा सकता है और फिर पीडब्लू-13 के प्रवेश पर अचानक अपनी कुर्सी पर गिर सकता है। इस संबंध में, हमने अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य, विशेष रूप से पीडब्लू-13 के साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।वह, अभियुक्त को साबित करने वाली एकमात्र गवाह होने के नाते, उसके साक्ष्य पर कुछ सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और हम उसके लिए अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ झूठा बयान देने का कोई

कारण नहीं पाते हैं।इस प्रकार, इस बात की पूरी संभावना है कि सुश्री रुचिका को अपीलकर्ता द्वारा पीडब्लू-13 द्वारा वर्णित तरीके से अपनाया जा सकता था।

21. उच्च न्यायालय, पूरे साक्ष्य की उचित पुनः सराहना पर, सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सफल रहा और भा.दं.सं. सी. की खंड 354 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया।दुनिया में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में विनाशकारी वृद्धि हुई है और हमारा देश भी इसका अपवाद नहीं है।हालाँकि वैधानिक प्रावधान ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई प्रदान करते हैं, लेकिन यह अंततः अदालतों को तय करना है कि ऐसी घटना हुई है या नहीं।अदालतों को साक्ष्य की सराहना करने में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और अभियुक्त को केवल तुच्छ आधारों पर छूट नहीं दी जानी चाहिए।सुश्री आराधना (पीडब्लू-13) के सुसंगत साक्ष्य से, अभियोजन पक्ष ने भा.दं.सं. सी. की खंड 354 के तहत अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है, भा.दं.सं. सी. की खंड 354 के तहत आरोप ऐसा है जिसे बनाना बहुत आसान है और इसका खंडन करना बहुत मुश्किल है।ऐसा नहीं है कि अपीलकर्ता और श्री दुग्गल और श्री ओझा के बीच कथित शत्रुता के कारण उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया था। हालाँकि, एक रूढ़िवादी समाज में यह असामान्य होगा कि एक महिला को प्रतिशोध लेने के लिए मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।जब अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा याचिका दायर की जाती है कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है, तो अदालतों का कर्तव्य होता है कि वे साक्ष्य की गहरी जांच करें और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की स्वीकार्यता या अन्यथा तय करें।तत्काल मामले में, निचली अदालत और उच्च निचली अदालत दोनों ने ऐसा किया है।नीचे दी गई अदालतों द्वारा पहले से लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण लेने की कोई गुंजाइश नहीं है।प्रत्यक्ष कृत्य की घटना अच्छी तरह से साबित होती है।प्रत्यक्षदर्शी की निर्दोष गवाही द्वारा-Ms.Aradhana

(PW-13)।

22. भा.दं.सं. सी. की खंड 354 के तहत अपराध का गठन आदेशने के लिए, केवल यह जानना कि एक महिला की शील भंग होने की संभावना है, केवल अपने उद्देश्य के लिए इस तरह का आक्रोश आदेशने के किसी भी जानबूझआदेश इरादे के बिना पर्याप्त है।विनम्रता की कोई संक्षिप्त सार अवधारणा नहीं है जो सभी मामलों पर लागू हो सकती है।विनम्रता के अपमान का आरोप लगाने वाले मामले से निपटने के दौरान अदालत को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा।भा.दं.सं. सी. की खंड 354 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व निम्नानुसार हैंः

(क) कि हमला किया गया व्यक्ति एक महिला होनी चाहिए;

((ख) कि अभियुक्त ने उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया होगा; और

((ग) महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया होगा।

23. यह न्यायालय, विद्याधरन बनाम केरल राज्य (2004) 1 एस. सी. सी. 215 में, निम्नानुसार अभिनिर्धारित करता हैः

“10. इरादा भा.दं.सं. सी. की खंड 354 के तहत दंडनीय अपराध का एकमात्र मानदंड नहीं है, और यह किसी भी महिला पर हमला करने या आपराधिक बल का उपयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, अगर वह जानता है कि इस तरह के कार्य से महिला की विनम्रता प्रभावित होने की संभावना है।ज्ञान और इरादा अनिवार्य रूप से मन की चीजें हैं और इन्हें भौतिक वस्तुओं की तरह प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है।इरादे या ज्ञान के अस्तित्व को उन विभिन्न परिस्थितियों से निकाला जाना चाहिए जिनमें

और जिन पर कथित अपराध का आरोप लगाया गया है।छेड़छाड़ और आक्रोश की शिकार एक पीड़ित गवाह के समान स्थिति में होती है और उसकी गवाही को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए।

24. यह निस्संदेह सही है कि यदि इरादा या ज्ञान किसी भी अपराध के घटकों में से एक है, तो इसे किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अन्य घटकों की तरह साबित करना होगा।लेकिन, यह भी उतना ही सच है कि मन की स्थिति होने के कारण उन तत्वों को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता है और किसी दिए गए मामले की उपस्थित परिस्थितियों से उनका अनुमान लगाना पड़ सकता है।घटनाओं का क्रम जो हमने पहले विस्तृत किया है, इंगित करता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त का अपेक्षित दोषपूर्ण इरादा था।

25. इस न्यायालय ने तारकेश्वर साहू बनाम बिहार राज्य, (2006) 8 एस. सी. सी. 560 मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

> “39. जहां तक भा.दं.सं. सी. की खंड 354 के तहत अपराध का संबंध है, किसी महिला की शील भंग करने का इरादा या यह जानना कि आरोपी के कार्य से उसकी शील भंग होगी, अपराध की गंभीरता है।"
>
> 40. एक महिला की विनम्रता का सार उसका लिंग है।अभियुक्त का दोषपूर्ण इरादा मामले का सार है।महिला की प्रतिक्रिया बहुत प्रासंगिक है, लेकिन इसकी अभावि हमेशा निर्णायक नहीं होती है।विनम्रता एक वर्ग के रूप में महिला मनुष्यों से जुड़ी एक विशेषता है।यह एक ऐसा गुण है जो एक महिला को उसके लिंग के कारण संलग्न करता है।”

26. एस. एच. ओ. के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने में लगभग 6 दिनों की देरी के संबंध में, इस न्यायालय का विचार है कि इसे विधिवत समझाया गया है।भारत में

एक परंपरा से बंधे गैर-अनुमति समाज में, यह स्वीकार करने में बेहद हिचकिचाहट होगी कि कोई भी घटना जो किसी महिला की पवित्रता को प्रतिबिंबित करने की संभावना है, समाज द्वारा बहिष्कृत होने या समाज द्वारा नीचा देखे जाने के खतरे के प्रति सचेत होने के कारण हुई थी।तत्काल मामले में, पीड़ित-रुचिका ने माता-पिता को इस परिस्थिति में घटना के बारे में सूचित नहीं किया कि अपीलार्थी-आरोपी, जो राज्य का एक बहुत ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, उचित था और उसके लिए बोलने का निर्णय आसान नहीं होता।मानवीय आचरण के सामान्य क्रम में, यह अविवाहित नाबालिग लड़की, उस दर्दनाक अनुभव का प्रचार नहीं करना चाहेगी जिससे वह गुजरी है और घटना के संबंध में अपने माता-पिता और अन्य लोगों को यह बताने के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस करती है जो शर्म की भावना से अभिभूत हैं और उसका स्वाभाविक झुकाव किसी से भी इसके बारे में बात करने से बचना होगा, ऐसा न हो कि परिवार का नाम और सम्मान विवाद में आ जाए।उसके माता-पिता को घटना की सूचना देने के बाद, निवासियों और साथी खिलाड़ियों द्वारा तुरंत अनुवर्ती कार्रवाई की गई और अपीलकर्ता-आरोपी के खिलाफ आरोपों वाला एक ज्ञापन तैयार किया गया और तत्कालीन सचिव (गृह) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।इसलिए, अपीलार्थी-अभियुक्त पर उचित विचार करते हुए, एक बार जब पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों को वरिष्ठ अधिकारियों से न्यायाधीश का आश्वासन मिल गया, तो उन्होंने अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

27. अपीलार्थी-अभियुक्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के इस तर्क के संबंध में कि ज्ञापन पर सुश्री रुचिका के हस्ताक्षर जाली थे, हालांकि उन्होंने श्री आनंद प्रकाश, श्री एस. सी. गिरहोत्रा, सुश्री आराधना और श्रीमती मधु प्रकाश के सामने हस्ताक्षर किए थे और उन्होंने यह स्वीकार किया है, हमारी राय है कि हस्तलेखन के बारे में विशेषज्ञ साक्ष्य केवल राय का प्रमाण है और यह कभी भी निर्णायक नहीं हो सकता है।किसी भी

विशेषज्ञ के साक्ष्य पर कार्य करते हुए, यह आमतौर पर यह देखने के लिए होता है कि क्या उस साक्ष्य की पुष्टि या तो स्पष्ट, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा की जाती है। एक हस्तलेखन विशेषज्ञ का एकमात्र साक्ष्य आम तौर पर किसी निश्चित व्यक्ति के लेखन के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है।एक अदालत किसी व्यक्ति के विवादित लेखन की तुलना दूसरों के साथ करने में सक्षम है जो उसके लेखन के रूप में स्वीकार या साबित होते हैं।किसी अदालत के लिए किसी व्यक्ति के लेखन के बारे में निष्आदेश को केवल विशेषज्ञ तुलना के आधार पर किसी निश्चित दस्तावेज में दर्ज आदेशना सुरक्षित नहीं हो सकता है, लेकिन एक अदालत स्वयं लेखन की तुलना आदेश सकती है ताकि उस संबंध में उसके सामने पेश किए गए अन्य साक्ष्यों की ठीक से सराहना की जा सके।एक हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय साक्ष्य अधिनियम की खंड 45 को देखते हुए भी प्रासंगिक है, लेकिन वह भी निर्णायक नहीं है।इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि एक हस्तलेखन विशेषज्ञ का एकमात्र साक्ष्य आम तौर पर किसी निश्चित व्यक्ति के लेखन के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है।यह इस प्रकार है कि यह आवश्यक नहीं है कि विवादित लेखन को साबित करने या गलत साबित करने के लिए किसी मामले में हस्तलेखन विशेषज्ञ की जांच की जानी चाहिए। यह राय साक्ष्य है और यह शायद ही कभी, यदि कभी भी, ठोस साक्ष्य का स्थान ले सकता है।इस तरह के साक्ष्य पर कार्रवाई करने से पहले, यह देखना सामान्य है कि क्या इसकी पुष्टि या तो स्पष्ट, प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा की जाती है।

28. मोबारिक अली अहमद बनाम। बॉम्बे राज्य ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 857, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-

"11.....विद्वान वकील ने सबूत के सवाल पर इस दृष्टिकोण पर

आपत्ति जताई।हालाँकि, हम कोई आपत्ति नहीं देख पा रहे हैं।दस्तावेज़ की वास्तविकता का प्रमाण दस्तावेज़ के लेखन का प्रमाण है और किसी अन्य तथ्य के समान तथ्य का प्रमाण है।उससे संबंधित साक्ष्य प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य हो सकते हैं।इसमें उस व्यक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकता है जिसने दस्तावेज़ को लिखा हुआ या हस्ताक्षर किए हुए देखा हो।यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 और 47 में प्रदान किए गए तरीकों में से एक द्वारा सामग्री की लिखावट या हस्ताक्षर का प्रमाण हो सकता है। इसे दस्तावेज़ की सामग्री द्वारा प्रदान किए गए आंतरिक साक्ष्य द्वारा भी साबित किया जा सकता है।सामग्री द्वारा सबूत का यह अंतिम तरीका काफी मूल्यवान हो सकता है जहां विवादित दस्तावेज़ पत्राचार की एक श्रृंखला में एक कड़ी होने का तात्पर्य रखता है, जिसमें कुछ लिंक अदालत की संतुष्टि के लिए साबित होते हैं।ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो दस्तावेज़ का प्राप्तकर्ता है, चाहे वह पत्र हो या तार, लेखन के बारे में अपने पूर्व ज्ञान या कथित प्रेषक के हस्ताक्षर दोनों के संदर्भ में एक उचित रूप से अच्छी स्थिति में होगा, हालांकि यह हो सकता है, और पत्राचार की श्रृंखला के विषय वस्तु के बारे में उसका ज्ञान भी, इसके लेखक से बात करने के लिए।एक उपयुक्त मामले में अदालत यह निर्णय करने की स्थिति में भी हो सकती है कि क्या दस्तावेज़ पत्राचार की श्रृंखला में एक वास्तविक कड़ी का गठन करता है और इस प्रकार इसके लेखक को निर्धारित करने के लिए।इसलिए, हम यह कहने में असमर्थ हैं कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नीचे की अदालतों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण कि पत्र वास्तविक हैं, किसी भी गंभीर कानूनी आपत्ति के लिए खुला है।प्रश्न, यदि कोई हो, केवल उस सामग्री की पर्याप्तता के बारे में हो सकता है जिस पर पत्रों की वास्तविकता के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है।लेकिन यह एक ऐसा मामला

है जिसका हम अपने सामने प्रचार करने की अनुमति नहीं दे सकते।

29. श्रीमती में। भगवान कौर बनाम श्री महाराज कृष्ण शर्मा और अन्य (1973) 4 एस. सी. सी. 46, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

> "26. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने हस्तलेखन विशेषज्ञ के साक्ष्य का नेतृत्व किया कि कैसे (पीडब्लू 1/ए) और मृतक के अन्य स्वीकृत लेखन के बीच लिखावट की समानता है, लेकिन इस संबंध में, हमारी राय है कि मामले की मुख्य आवश्यक विशेषताओं को देखते हुए, विशेषज्ञ साक्ष्य को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता है।एक हस्ताक्षर विशेषज्ञ का साक्ष्य, एक फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ के विपरीत, आम तौर पर एक कमजोर चरित्र का होता है और इसकी गलतियों पर अक्सर ध्यान दिया गया है इसलिए अदालतों को हस्ताक्षर विशेषज्ञ के साक्ष्य को बहुत अधिक महत्व देने से सावधान रहना चाहिए।श्री श्री किशोर चंद्र सिंह देव बनाम बाबू गणेश प्रसाद भगत मामले में इस न्यायालय ने कहा कि केवल लिखावट की तुलना के आधार पर सबसे अच्छा अनिर्णायक होना चाहिए और मामले में सकारात्मक साक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए।"

30. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक हस्तलेखन विशेषज्ञ का अप्रमाणित साक्ष्य एक अत्यंत कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और इसे दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के लिए निर्भर नहीं किया जाना चाहिए।इसलिए, अदालतों को हस्तलेखन विशेषज्ञ के साक्ष्य को बहुत अधिक महत्व देने से सावधान रहना चाहिए।यह शायद ही कभी, यदि कभी भी, ठोस साक्ष्य का स्थान ले सकता है।इस तरह के साक्ष्य पर कार्रवाई करने से पहले, यह देखना सामान्य है कि क्या इसकी पुष्टि या तो स्पष्ट, प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा की जाती है।

31. यह अपीलार्थी-अभियुक्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का दावा है कि वर्तमान मामला मनगढ़ंत है और एच. एल. टी. ए. और एच. टी. ए. के बीच प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है। इसके अलावा, श्री आनंद प्रकाश ने अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ अपनी लंबे समय से चली आ रही दुर्भावना को दूर करने के अलावा इस अभ्यास से पेशेवर लाभ प्राप्त किया है।यह तर्क के अनुरूप नहीं है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, कोई भी पिता अपनी बेटी के सम्मान और प्रतिष्ठा को केवल इसलिए नुकसान पहुँचाएगा क्योंकि उसके एक सहयोगी का अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ अपना एजेंडा है।हालांकि, प्रत्येक मामले को उसके तथ्यात्मक मैट्रिक्स की कसौटी पर निर्धारित किया जाना है।तत्काल मामले में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि पीड़ित की कम उम्र का शोषण श्री आनंद प्रकाश (पीडब्लू-1) के लाभ के लिए किया गया था

32. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता के इस तर्क के संबंध में कि दो महत्वपूर्ण स्थल गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है।, श्री पलटू-गेंद उठाने वाला और श्री आई. डी. 1-कोच अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालते हैं, उच्च न्यायालय ने सही कहा है कि अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष केवल तभी निकाला जा सकता है जब वह कुछ सबूतों को रोकता है, न कि केवल कुछ सबूत प्राप्त करने में विफलता के कारण।हमारी यह भी राय है कि वे किसी भी तरह से अपराध के वास्तविक अपराध से जुड़े नहीं थे और उनकी अभावि में भी, अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा छेड़छाड़ के अपराध का अपराध घटना के चश्मदीद गवाह (पीडब्लू-13) की निर्दोष गवाही से अच्छी तरह से साबित होता है।

33. एक निश्चित तथ्य को साबित करने के लिए गवाहों की किसी विशेष संख्या की आवश्यकता नहीं है।गवाहों की मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता मायने रखती है।साक्ष्य को तौला जाता है और गिना नहीं जाता है।एक चश्मदीद गवाह का भी प्रमाण, सच्चा,

निरंतर और प्रेरक आत्मविश्वास दृढ़ विश्वास बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त के अपराध को साबित आदेशने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा उन सभी व्यक्तियों से पूछताछ की जानी चाहिए जो घटनास्थल पर मौजूद थे। सभी गवाहों से पूछताछ करने के बाद, भले ही पास में मौजूद अन्य व्यक्तियों से पूछताछ न की गई हो, चश्मदीद गवाह के साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है।

34. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि सुश्री आराधना (पीडब्लू-13) ने शुरू से अंत तक अपनी गवाही का विरोध किया और उनके बयान को अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के साथ विश्वसनीय और पुष्टि करने वाला पाया गया और नीचे दी गई दोनों अदालतें भा.दं.सं. सी. की खंड 354 के तहत अपीलकर्ता-अभियुक्त की दोषसिद्धि को बरकरार रखने में सही थीं।

35. अपीलार्थी-अभियुक्त की सजा के संबंध में, उनकी ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कुछ कम करने वाले कारकों की ओर इशारा किया है जो हैं-अपीलार्थी-अभियुक्त की वृद्धावस्था, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, 'जन्मजात हृदय रोग' से पीड़ित अविवाहित बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी, पिछली सराहनीय सेवा और लंबे समय तक मुकदमा।उपरोक्त कारकों, विशेष रूप से अपीलार्थी-अभियुक्त की वृद्धावस्था और शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम उसे वापस जेल में डालना समीचीन नहीं समझते हैं।जबकि हम अपीलार्थी-अभियुक्त के अपराध के बारे में निष्कर्षों को बरकरार रखते हैं, हमारी राय है कि न्यायाधीश का कारण सबसे अच्छा होगा जब अपीलार्थी-अभियुक्त की सजा को पहले से गुजर चुकी अवधि में बदल दिया जाएगा।इसलिए, हम अपीलकर्ता की सजा को उसकी बहुत अधिक उम्र को ध्यान में रखते हुए एक विशेष मामले के रूप में पहले से गुजर चुकी अवधि तक कम कर देते हैं।

36. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम सजा को पहले से गुजर चुकी

अवधि में संशोधित करते हुए भा.दं.सं. सी. की खंड 354 के तहत अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हैं।अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों के साथ किया जाता है।

देविका गुजराल अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।